

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग- 5

देहरादून,

दिनांक: 06 जून, 2016

विषय: जनपद देहरादून के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालसी, के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7प/1/8/2010/5986 दिनांक 18मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या-846/XXVIII-5-2011-07 (घो0)/2009 दिनांक 16 जून, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालसी, जनपद देहरादून के भवनों के निर्माण कार्यों पुनरीक्षित आगणन की अनुमोदित ₹486.00 लाख (सिविल कार्यों की लागत ₹457.47 लाख तथा अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यों की लागत ₹28.53 लाख) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष देयता ₹169.29 लाख (₹486.00 लाख + ₹290.71 लाख) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में सुसंगत मद में प्रावधानित धनराशि ₹50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) शासनादेश संख्या-846/XXVIII-5-2011-07(घो0)/2009 दिनांक 16 जून, 2011 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इसके पश्चात उक्त कार्य की पुनरीक्षित लागत किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी।
2. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) एवं समय-समय पर वित्तीय मितव्ययता हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाये, 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 02-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश), 24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

(2)

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-17(P)/XXVII(3)/2016-17 दिनांक 03 जून, 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या-S1606120056

भवदीय,

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव

संख्या- 704 (1)/XXVIII-5-2016-07(घो0)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकास नगर, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी01
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव